



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 12—दिसम्बर 18, 2009 (अग्रहायण 21, 1931)
 No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 12—DECEMBER 18, 2009 (AGRAHAYANA 21, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

	विषय-सूची	
भाग I—खण्ड-1—	(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1113
भाग I—खण्ड-2—	(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1163
भाग I—खण्ड-3—	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	77
भाग I—खण्ड-4—	रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी को गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1857
भाग II—खण्ड-1—	अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड-1क—	अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड-2—	विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड-3—	उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियाँ आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—	भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियाँ आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—	भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियाँ आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग III—खण्ड-1—	उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी को गई अधिसूचनाएं	4279
भाग III—खण्ड-2—	पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी को गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*
भाग III—खण्ड-3—	मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी को गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड-4—	विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक नियमों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	11901
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों	द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	411
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*	

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1113	than the Administration of Union Territories).....*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1163	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	77	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1857	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....*	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs.....*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.....*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills.....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.....
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other	411	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi.....*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 2009

सं. 120-प्रेज/2009-आईसी-16664—मेजर जनरल पट्टुगुन्ट सिक्यराम कृष्ण चौधरी को इस सचिवालय द्वारा 26 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं. 60-प्रेज/2001 के अन्तर्गत प्रदान किया गया अति विशिष्ट सेवा पदक एतद्वारा रद्द किया जाता है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 नवम्बर 2009

आईएसओ/आईईसी-14496-ओएफएफ (मुक्त फोन्ट प्ररूप)

सं. 2(32)/2009-ईजी-II—जबकि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) का प्रवर्तन कर रहा है जिसका उद्देश्य सही शासन एवं सांस्थानिक तन्त्र तैयार करना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना है; और

जबकि एनईजीपी के अंतर्गत, भारत सरकार किसी प्रकार के प्रौद्योगिकीय अवरोध से बचने के लिए मुक्त मानकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है; और

जबकि ई-शासन में मानक एक उच्च प्राथमिकता वाला कार्यकलाप है, जिससे सूचना को आपस में बाँटने तथा विभिन्न ई-शासन अनुप्रयोगों में डेटा की अविछिन्न अंतर-प्रचालनीयता का सुनिश्चय होता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने ई-शासन के लिए मानक तैयार करने/अपनाने के उद्देश्य से एनईजीपी के अंतर्गत एक सांस्थानिक तंत्र का गठन किया है; और

जबकि स्थानीय भाषाओं में सूचना की उपलब्धता की कमी के कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में धीमी प्रगति हो रही है और आईसीटी के लाभ सामान्य जनता तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अतः “भाषा प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण” एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर मानकीकरण के अंतर्गत ध्यान दिया जा रहा है; और

जबकि मानकों से संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने आईएसओ/आईईसी-14496-ओएफएफ (मुक्त फोन्ट प्ररूप) को फोन्ट के मानक के रूप में अनुमोदित कर दिया है जो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पर आधारित है तथा डेटा भण्डारण के लिए यूनिकोड का अनुपालन करता है। इससे विभिन्न अनुप्रयोगों तथा स्लेटफॉर्मों पर डेटा को ले जाना सुनिश्चित होता है; और इसलिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एतद्वारा आईएसओ/

आईईसी-14496-ओएफएफ (मुक्त फोन्ट प्ररूप) को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ई-शासन अनुप्रयोगों के मामले में सभी 22 भारतीय भाषाओं के लिए मानक फोन्ट के रूप में अधिसूचित करता है।

एस. एस. रावत
संयुक्त निदेशक

यूनिकोड 5.1.0

सं. 2(32)/2009-ईजी-II—जबकि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) का प्रवर्तन कर रहा है जिसका उद्देश्य सही शासन एवं सांस्थानिक तन्त्र तैयार करना तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं का कार्यान्वयन करना है; और

जबकि एनईजीपी के अंतर्गत, भारत सरकार किसी प्रकार के प्रौद्योगिकीय अवरोध से बचने के लिए मुक्त मानकों के प्रयोग को बढ़ावा दे रही है; और

जबकि ई-शासन में मानक एक उच्च प्राथमिकता वाला कार्यकलाप है, जिससे सूचना को आपस में बाँटने तथा विभिन्न ई-शासन अनुप्रयोगों में डेटा की अविछिन्न अंतर-प्रचालनीयता का सुनिश्चय होता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने ई-शासन के लिए मानक तैयार करने/अपनाने के उद्देश्य से एनईजीपी के अंतर्गत एक सांस्थानिक तंत्र का गठन किया है; और

जबकि स्थानीय भाषाओं में सूचना की उपलब्धता की कमी के कारण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्षेत्र में धीमी प्रगति हो रही है और आईसीटी के लाभ सामान्य जनता तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। अतः “भाषा प्रौद्योगिकी का स्थानीयकरण” एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर मानकीकरण के अंतर्गत ध्यान दिया जा रहा है; और

जबकि सक्षम प्राधिकारी ने यूनिकोड 5.1.0 को अक्षर कोडीकरण मानक के रूप में अनुमोदित कर दिया है जिसे बहुभाषी पाठ के प्रस्तुतीकरण के लिए पूरे विश्व में व्यापक स्वीकृति प्राप्त है और जो भारतीय भाषाओं का भी समर्थन करता है और इसके साथ ही साथ यह संविधान द्वारा स्वीकृत सभी भारतीय भाषाओं के लिए अनुप्रयोगों के स्थानीयकरण को सरल बनाएगा; और

इसलिए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एतद्वारा यूनिकोड 5.1.0 तथा इसके सभी भावी संस्करणों को इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से ई-शासन अनुप्रयोगों के मामले में मानक के रूप में अधिसूचित करता है।

एस. एस. रावत
संयुक्त निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th November 2009

No. 120-Pres./2009—The Ati Vishisht Seva Medal awarded to IC-16664 Major General Puttagunta Sivarama Krishna Choudhary vide this Secretariat Notification No. 60-Pres/2001 dated 26 January, 2001 is hereby cancelled.

BARUN MITRA

Joint Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 27th November 2009

ISO/IEC-14496-OFF (Open Font Format)

No. 2(32)/2009-EG-II—Whereas Department of Information Technology (DIT), Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (GoI) is driving the National e-Governance Plan (NeGP) which seeks to create the right Governance and Institutional Mechanism and implement a number of Mission Mode Projects at the Centre and State Government; and

Whereas under NeGP, GoI is promoting the usage of Open Standards to avoid any technology lock-ins; and

Whereas Standards in e-Governance are a high priority activity, which will help ensure sharing of information and seamless interoperability of data across e-Governance applications. DIT, GoI has set up an Institutional Mechanism under NeGP to evolve/adopt Standards for e-Governance; and

Whereas because of the lack of availability of information in local language there has been a slow progress in the Information and Communication Technology (ICT) sector and the benefits of ICT have not percolated down to the common man. Hence, "Localization and Language Technology" is an important area which is being addressed under Standardization; and

Whereas the Competent Authority on Standards has approved ISO/IEC-14496-OFF (Open Font Format) as the Font Standard which is based on a single International Standard and comply with UNICODE for data storage. This ensures data portability across various applications and platforms; and

Therefore, Department of Information Technology, Government of India hereby notifies ISO/IEC-14496-OFF (Open

Font Format) as the Font Standard for e-Governance Applications for all the 22 Indian Languages w.e.f. the date of notification.

S. S. RAWAT
Joint Director

Unicode 5.1.0

No. 2(32)/2009-EG-II—Whereas Department of Information Technology (DIT), Ministry of Communications and Information Technology, Government of India (GoI) is driving the National e-Governance Plan (NeGP) which seeks to create the right Governance and Institutional Mechanism and implement a number of Mission Mode Projects at the Centre and State Government; and

Whereas under NeGP, GoI is promoting the usage of Open Standards to avoid any technology lock-ins; and

Whereas Standards in e-Governance are a high priority activity, which will help ensure sharing of information and seamless interoperability of data across e-Governance applications. DIT, GoI has set up an Institutional Mechanism under NeGP to evolve/adopt Standards for e-Governance; and

Whereas because of the lack of availability of information in local language there has been a slow progress in the Information and Communication Technology (ICT) sector and the benefits of ICT have not percolated down to the common man. Hence, "Localization and Language Technology" is an important area which is being addressed under Standardization; and

Whereas the Competent Authority on Standards has approved Unicode 5.1.0 as Character Encoding Standard which is widely recognized all over the world for representation of multilingual text and also supports Indian Languages as well as will ease Localization of applications for all the constitutionally recognized Indian languages; and

Therefore, Department of Information Technology, Government of India hereby notifies Unicode 5.1.0 and its future versions as the Standard for e-Governance Applications w.e.f. the date of notification.

S. S. RAWAT
Joint Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009